भारत सरकार

उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1171

16 अगस्‍त, **201**3के लिए प्रश्न

चीनी उत्‍पादन के लिए गन्‍ने की उपलब्‍धता

1171. श्रीमोहम्‍मद अली खान:

 श्रीमती टी0 रत्‍नाबाई:

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्‍या सूखा पड़ने तथा चारे के रूप में गन्‍ने का इस्‍तेमाल किए जाने के कारण चीनी उत्‍पादन हेतु आवश्‍यक गन्‍ने की उपलब्‍धता कम हो गई है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है तथा इसकी वर्तमान स्‍थिति क्‍या है; और**

**(ग) अब तक क्‍या सुधारात्‍मक कदम उठाए गए हैं?**

**उत्तर**

# उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**(प्रो0 के0वी0 थॉमस)**

(**क): और** (**ख): महाराष्‍ट्र और कर्नाटक के गन्‍ना आयुक्‍तों ने अपने राज्‍यों में चारे के रूप में गन्‍ने के विपथन और सूखे के कारण 2012-13 चीनी मौसम के दौरान चीनी उत्‍पादन के लिए गन्‍ने की उपलब्‍धता में कमी होने की सूचना दी है। तमिलनाडु के गन्‍ना आयुक्‍त ने भी सूखे की स्‍थिति के कारण चीनी उत्‍पादन के लिए गन्‍ने की उपलब्‍धता में कमी होने की सूचना दी है। जुलाई, 2013 में जारी कृषि एवं सहकारिता विभाग के चतुर्थ अग्रिम आकलनों के अनुसार गन्‍ने का उत्‍पादन 2012-13 चीनी मौसम के लिए 3389.63 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि पिछले चीनी मौसम 2011-12 के दौरान गन्‍ने का उत्‍पादन 3610.37 लाख टन था।**

**(ग): महाराष्‍ट्र सरकार के गन्‍ना आयुक्‍त ने सूचित किया है कि गन्‍ने की उत्‍पादकता में सुधार करने के लिए वे चीनी मिलों को किसानों के माध्‍यम से गन्‍ना फसल के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने और अगले 3-4 वर्षों के दौरान 100 प्रतिशत क्षेत्र को ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए प्रोत्‍साहित कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार के गन्‍ना आयुक्‍त ने सूचित किया है कि गन्‍ने में ड्रिप सिंचाई को अपनाने के लिए वे 75 प्रतिशत सब्‍सिडी बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्‍त, राज्‍य कृषि विश्‍वविद्यालय और संस्‍थान उपलब्‍ध प्रौद्योगिकियों का प्रचार कर रहे हैं जिससे कि जल के अभाव की स्‍थितियों के अंतर्गत गन्‍ने में सुधार हो सके। तमिलनाडु राज्‍य में सूखा प्रबंधन प्रथाओं, ड्रिप सिंचाई और सतत गन्‍ना पहलों को सुधारात्‍मक उपायों के रूप में अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, केन्‍द्रीय सरकार चीनी मिलों को गन्‍ना विकास के लिए जिसमें बेहतर सिंचाई सुविधाएं, उन्‍नत बीज किस्‍में, पेडी प्रबंधन शामिल हैं इत्‍यादि के लिए शर्करा विकास निधि से रियायती ऋण प्रदान करती है।**

**\*\*\*\*\***